बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 111

## एमएसएमई : राहत भी सवाल भी

**घरेलू** सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों (एमएसएमई) की दिक्कतों पर नजर डालने के लिए गठित भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की एक समिति ने कई ऐसे उपाय सुझाए हैं जो काबिले तारीफ हैं। इनमें 5,000 करोड़ रुपये मूल्य का संकटग्रस्त परिसंपत्ति फंड बनाने का विचार शामिल है जो टेक्सटाइल अपग्रेडेशन फंड स्कीम के तर्ज पर काम कर सकता है। समिति ने यह भी कहा कि एमएसएमई के विभिन्न प्राधिकार के समक्ष पंजीयन के बजाय ज्यादातर गतिविधियों के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) को ही पर्याप्त कर दिया जाना चाहिए। उसके मुताबिक पूरा ध्यान बाजार की सुविधा प्रदान करने और क्षेत्र में कारोबारी सुगमता लाने पर केंद्रित किया जाना चाहिए। समिति ने सुझाव दिया कि एमएसएमई की देरी से भुगतान होने की दिक्कत समाप्त करने के लिए एमएसएमई अधिनियम में संशोधन करके सभी एमएसएमई के लिए एक खास राशि से ऊपर के इनवॉइस अपलोड करना अनिवार्य किया जाना चाहिए। समिति विभिन्न संस्थानों के समक्ष विविध पंजीयन के खिलाफ है। यह न केवल जटिल है बल्कि इससे प्रयासों का दोहराव भी होता है। एक अन्य रोचक सुझाव में पैनल ने सरकार से 10,000 करोड़ रुपये के सरकार प्रायोजित कोष की अनुशंसा की है ताकि इस क्षेत्र में निवेश करने वाले वेंचर कैपटल और प्राइवेट इक्विटी फंड की सहायता की जा सके। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को ऐसा मंच बनाने में सुविधा प्रदाता की भूमिका निभानी चाहिए। इससे एमएसएमई की सहायता हो सकती है क्योंकि यह क्षेत्र काफी हद तक इक्विटी के लिए असंगठित स्रोतों पर निर्भर करता है। इसमें स्वयं की बचत और परिवारों और मित्रों से मिलने वाली फंडिंग शामिल है।

समिति के सुझाव व्यापक तौर पर उपयोगी हैं क्योंकि एमएसएमई क्षेत्र को मदद की आवश्यकता तो है। फंड का असमान वितरण भी हमारी अर्थव्यवस्था की एक बड़ी समस्या है। एमएसएमई को बहुत कम पूंजी आवंटित हुई है क्योंकि वाणिज्यिक बैंक ऐसे ऋण को बहुत जोखिम भरा समझते हैं। आरबीआई की ताजा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में भी छोटे कारोबार को दिए जाने वाले ऋण को लेकर चिंता जताई गई है। वर्ष 2017-18 के बीच एमएसएमई को खूब ऋण दिया गया। आरबीआई की रिपोर्ट में इस ऋण को रेखांकित करते हुए सुझाव दिया गया कि ऋण में इतनी अधिक बढ़ोतरी के चलते ऋण देने के मानकों में शिथिलता की जांच की स्थिति बनती है। उसने बैंकों की निगरानी की नीति की बात भी कही।

इस संदर्भ में पैनल का गारंटी रहित ऋण को दोगुना करने का सुझाव जोखिम भरा हो सकता है। इस सुझाव में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और स्वयं सहायता समूह आधारित संस्थान भी शामिल हैं। माइक्रो यूनिट्स ऐंड रीफाइनैंस एजेंसी (मुद्रा) ऋण योजना में बेहतर ऋण मानकों की अनदेखी की गई। ऋण की वसूली भी एक चुनौती है। मुद्रा ऋण योजना के आने वाले दिनों में फंसे हुए कर्ज का बड़ा स्रोत होने की आशंका नजर आने लगी है। मार्च 2019 में समाप्त वित्त वर्ष में योजना का फंसा हुआ कर्ज 69 फीसदी बढ़कर 16,480.87 करोड़ रुपये हो गया जबकि एक साल पहले यह मात्र 9,769 करोड़ रुपये था। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के मुताबिक योजना में फंसे हुए कर्ज का अनुपात अब तक के अनुमान से काफी अधिक हो सकता है। मुद्रा ऋण लेने वाले कर्जदारों की प्रकृति अस्थिर और चक्रीय होने के कारण संदेह के दायरे में है वहीं फंसे हुए कर्ज में इजाफा बताता है कि बैंक न तो सही ढंग से निगरानी कर रहे हैं और न ही समय पर पुनर्भुगतान हो पा रहा है। ध्यान रहे कि निजी क्षेत्र के बैंकों का प्रदर्शन इस मोर्चे पर भी सरकारी बैंकों से बेहतर है। कुल मिलाकर गारंटी रहित ऋण से समस्या हल होने वाली नहीं है।

अजय मोहंती

# एफडीआई की बढ़े आवक साथ आएं सभी अंशधारक

देश की अर्थव्यवस्था में एफडीआई की अहम भूमिका है। आवश्यकता इस बात की है कि एफडीआई को लेकर एक सुविचारित और स्पष्ट नीति हो जो सभी अंशधारकों को साथ लाए। विस्तार से बता रहे हैं **राजीव कुमार**

लगातार दो वर्ष तक 60 अरब डॉलर पर ठहरे रहने के बाद वर्ष 2018-19 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सकल आवक बढ़कर 64.37 अरब डॉलर हो गई। यह बात उल्लेखनीय है कि तमाम आर्थिक उतार-चढ़ाव के बावजूद विदेशी निवेशकों ने भारत में भरोसा बनाए रखा। वर्ष 2006-07 के बाद से एफडीआई निवेश में तीन गुना इजाफा इस बात का प्रतीक है। उस वक्त यह राशि 22.8 अरब डॉलर थी। बहरहाल शुद्ध एफडीआई आवक पर ध्यान देना आवश्यक है क्योंकि ये वास्तव में हमारी बाहरी खाते को संतुलित बनाने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम करते हैं।

अच्छी खबर यह है कि वर्ष 2018-19 में शुद्ध एफडीआई आवक भी 2017-18 के 39.43 अरब डॉलर से बढ़कर 45.28 अरब डॉलर हो गई। वर्ष 2019 में 15 फीसदी की वृद्धि दर के साथ यह बढ़ोतरी उल्लेखनीय तो है ही, बीते दो वर्ष के एकदम विपरीत भी है। उन दो वर्षों में शुद्ध एफडीआई आवक में क्रमश: 6 और 6.6 फीसदी की गिरावट आई थी। ऐसे में 2018-19 की शुद्ध आवक को अच्छी वापसी माना जा सकता है क्योंकि यह 2015-16 के 44.9 अरब डॉलर के अब तक के उच्चतम स्तर को भी पार कर गई।

यह बात ध्यान देने लायक हो सकती है कि अंकटाड (वैश्विक निवेश रिपोर्ट) के मुताबिक भारत अब सर्वाधिक एफडीआई आवक करने वाले देशों में 10वें स्थान पर है। अमेरिका 2018 में 252 अरब डॉलर के एफडीआई के साथ शीर्ष पर है। वैश्विक सीमा पार निवेश आवक में भारत की हिस्सेदारी 2010 के 2 फीसदी से बढ़कर 2018 में 3.2 फीसदी हो गई। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि विश्व बैंक के विकास सूचकांक आंकड़ों के मुताबिक देश के जीडीपी में शुद्ध एफडीआई आवक की हिस्सेदारी बीते वर्षों में काफी कम हो गई। सन 1999 में जहां यह जीडीपी के 3.6 फीसदी के उच्चतम स्तर पर थी, वहीं 2017 में यह गिरकर 1.6 फीसदी रह गई। वर्ष 2018-19 में इसने वापसी की और आज यह बेहतर स्थिति में है। जीडीपी में हिस्सेदारी के रूप में देश का प्रदर्शन 2017 में चीन और अमेरिका के समतुल्य नजर आ रहा है। हालांकि हकीकत यह है कि उनका जीडीपी भारत की अर्थव्यवस्था के पांच गुना के बराबर है। वर्ष 2018 में चीन 129 अरब डॉलर की एफडीआई जुटाने में कामयाब रहा। यह स्पष्ट है कि सन 1982 में साहसी ढांचागत सुधारों के बाद से चीन का शानदार आर्थिक प्रदर्शन काफी हद तक एफडीआई पर निर्भर रही है।

यही कारण है कि चीन के जीडीपी में एफडीआई की आवक सन 1982 के 0.6 फीसदी से बढ़कर 1993 में 6.2 फीसदी हो गई थी। इस अवधि में चीन की प्रति व्यक्ति आय 203 डॉलर से बढ़कर 377 डॉलर हो गई। यह तब से लगातार बढ़ रही है।

हमारे मामले में सन 1982 में यह बेहद कम थी। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में एफडीआई सन 2008 में उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। उच्चतम स्तर पर रहते हुए भी देश के जीडीपी में एफडीआई की हिस्सेदारी चीन के उच्चतम स्तर के आधे से थोड़ी ही ज्यादा थी। सन 1982 में दोनों का स्तर समान था। स्पष्ट है कि हमने अतिरिक्त रोजगार तैयार करने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में विदेशी पूंजी निवेशकों पर निर्भरता चीन की तुलना में काफी पहले कम कर ली। इस संदर्भ में देखें तो शायद यह बात ध्यान देने लायक होगी कि सन 1991 में चीन और भारत की प्रतिव्यक्ति आय कमोबेश वैश्विक स्तर के 6-7 फीसदी के समान थी। सन 2018 तक चीन की प्रति व्यक्ति आय वैश्विक औसत के 85 फीसदी जबकि भारत की केवल 18 फीसदी रह गई थी। जाहिर सी बात है कि इससे हम काफी कुछ सीख सकते हैं।

इन बातों के बीच देश में एफडीआई आवक के एक गुणधर्म को चिह्नित करने की आवश्यकता है। सकल एफडीआई आवक में मौजूदा परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करने वाले ब्राउनफील्ड और नए रोजगार और नई क्षमता का निर्माण करने वाली ग्रीनफील्ड आवक शामिल होती है। पाठक ब्राउनफील्ड निवेश के हालिया उदाहरणों से परिचित होंगे। मिसाल के तौर पर फ्लिपकार्ट में वॉलमार्ट का 16 अरब डॉलर का निवेश, गैजप्रॉम द्वारा एस्सार रिफाइनरी का 12.9 अरब डॉलर में अधिग्रहण, जीटीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा 10.8 अरब डॉलर में रिलायंस कम्युनिकेशंस का अधिग्रहण। ऐसे 25 सौदों का आंकड़ा बताता है कि वर्ष 2007-08 से ऐसे ब्राउनफील्ड निवेश में 166 अरब डॉलर की राशि का प्रयोग किया गया। यह यकीनन कम अनुमानित है। वर्ष 2008 से 2018 के बीच अनुमानित ग्रीनफील्ड एफडीआई की राशि 255 अरब डॉलर रही। जबकि इस अवधि में ब्राउनफील्ड एफडीआई 262 डॉलर रहा। वास्तविक आंकड़े अनुमानित आंकड़ों से कमजोर रहे। एक विचित्र बात यह है कि दोनों तरह के एफडीआई की आवक को अलग-अलग करने वाले आंकड़े घरेलू तौर पर सरकारी या निजी स्रोतों से उपलब्ध नहीं हैं। एफडीआई के आंकड़ों को विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के आंकड़ों की तरह उपलब्ध कराने के लिए कुछ सुधार करना आवश्यक है।

एफडीआई की आवक को घरेलू निवेशकों पर विशेष तरजीह दिए जाने की आवश्यकता है। हमारी स्थिति चीन से काफी अलग है। चीन में निजी संपदा पर तीन दशकों तक लागू रही पुरातनपंथी रोकथाम के बाद उद्यमी प्रतिभाओं और निवेश करने लायक संसाधनों को तवज्जो मिली जबकि हमारे यहां उद्यमिता का समुदाय हमेशा फलता-फूलता रहा। इस समुदाय को निवेश भी मिला जो आम तौर पर घरेलू जमा पर आधारित था। एफडीआई का फाइनैंस हमारी कुल आय के बमुश्किल 5 फीसदी के लिए उत्तरदायी है।

अब हमें व्यापक तौर पर यह चर्चा करनी होगी कि ऐसी नीति को जारी रखने के क्या लाभ अथवा नुकसान हैं जो ग्रीनफील्ड एफडीआई आवक को आकर्षित करने का काम करती है। इस मामले में हमें अपनी स्थिति सुस्पष्ट करनी होगी ताकि सभी अंशधारक एक साथ आ सकें। इससे नीतिगत सुनिश्चितता तय होगी और एफडीआई को लेकर सभी स्तरों पर सटीक अनुमान लगाना संभव हो सकेगा। इस बहस में हमें निर्यात आधारित एफडीआई और टैरिफ को लेकर भी भेद करना होगा। इस विषय में अब तक जो भी जानकारी उपलब्ध है उसके मुताबिक निर्यातोन्मुखी एफडीआई का अर्थव्यवस्था पर कहीं अधिक व्यापक प्रभाव पड़ता है। अगर हमें देश की अर्थव्यवस्था को 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है तो ऐसी स्पष्ट, एकीकृत करने वाली और सटीक अनुमान लगाने वाली नीति अवश्य फायदा पहुंचाएगी।

*(लेखक नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। लेख में प्रस्तुत विचार निजी हैं।)*

# राष्ट्रपति का अभिभाषण और आर्थिक नीति से जुड़े सवाल

दिल्ली डायरी

ए के भट्टाचार्य

**बिना गारंटी के इतना अधिक ऋण वित्तीय क्षेत्र की सेहत के लिए ठीक नहीं है। इसकी अदायगी अनिश्चित होगी। खेद की बात है कि ऐसे ऋण का बोझ भी सार्वजनिक क्षेत्र के उन बैंकों को उठाना होगा, जो पहले ही संकट के दौर से गुजर रहे हैं**

**राष्ट्रपति** रामनाथ कोविंद ने गत गुरुवार को संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। इस दौरान मोदी सरकार के आर्थिक लक्ष्यों को सामने रखा गया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में आर्थिक मोर्चे पर क्या उम्मीद रखी जा सकती है, उसे समझने के लिए इस भाषण में किए गए वादों की जांच परख की जा सकती है। वर्ष 2024 तक देश की अर्थव्यवस्था का आकार 5 लाख करोड़ डॉलर करने के लक्ष्य को अखबारों में सुर्खियां मिलीं जिसे समझा जा सकता है।

इस बात पर सवाल उठने स्वाभाविक हैं कि यह भी सिर्फ एक जुमला है या सरकार वाकई में पांच साल में इतना महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल करने को लेकर गंभीर है। ध्यान रहे कि 5 लाख करोड़ डॉलर के लक्ष्य का जिक्र गत 15 जून को नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया था। मोदी ने यह स्वीकार किया था कि लक्ष्य चुनौतीपूर्ण है लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि इसे हासिल किया जा सकता है। उनका यह भी कहना था कि राज्यों को अपनी मूल क्षमता को पहचानना चाहिए और जिला स्तर से जीडीपी बढ़ाने की दिशा में काम करना चाहिए। राष्ट्रपति ने भी इस लक्ष्य को हासिल करने में राज्यों की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि यह लक्ष्य राज्यों के साथ मिलकर हासिल किया जा सकता है।

यह सच है कि तेज गति से विकसित हो रहे राज्य देश के समग्र आर्थिक विकास में मददगार हो सकते हैं। परंतु इस चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को हासिल करने के क्रम में राज्यों पर दायित्व सौंपना अहम है। संभव है कि ऐसा करके मोदी सरकार सहकारिता भरे संघवाद पर अपना यकीन दिखाना चाहती हो। यह बचाव का तरीका भी हो सकता है। अगर 5 लाख करोड़ डॉलर का लक्ष्य हासिल नहीं हुआ तो राज्यों को बलि का बकरा बनाया जा सकता है।

चाहे जो भी हो अतीत में वृद्धि के मोर्चे पर भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन ऐसा रहा है जो नए लक्ष्य को हासिल करने में कठिनाई के संकेत देता है। वर्ष 2013-14 में देश का जीडीपी डॉलर के हिसाब से 2 लाख करोड़ डॉलर था। 2018-19 में इसके बढ़कर 2.7 लाख करोड़ डॉलर होने का अनुमान है यानी 35 प्रतिशत का इजाफा। अगर 2024 तक 5 लाख करोड़ डॉलर के लक्ष्य को हासिल करना है तो इस अवधि में 85 फीसदी की दर से वृद्धि हासिल करनी होगी। यह आसान काम नहीं है। क्या इसे आधिकारिक लक्ष्य घोषित करने के पहले इस पर भलीभांति विचार किया गया?

राष्ट्रपति पहले ही यह स्वीकार कर चुके हैं कि भारत अब दुनिया में सबसे तेज गति से विकसित होती अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं रह गया। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेज विकसित होती अर्थव्यवस्था में से एक है। आरबीआई के गवर्नर ने भी स्वीकार किया कि देश में आर्थिक गतिविधियां कमजोर पड़ रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि वृद्धि दर हासिल करने में कुछ और तिमाहियां लगेंगी। जीडीपी वृद्धि के हालिया आंकड़े कोई आशा नहीं जगाते।

प्रश्न यह है कि ऐसा लक्ष्य तय ही क्यों किया गया? राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि इंडस्ट्री 4.0 को ध्यान में रखते हुए सरकार जल्दी ही नई औद्योगिक नीति जारी कर सकती है। यहां नई नीति के लिए इंडस्ट्री 4.0 का संदर्भ उल्लेखनीय है। चौथी औद्योगिक क्रांति ने तकनीक, स्वचालन, कृत्रिम मेधा और डेटा विश्लेषण को बढ़ावा दिया है। इसके साथ ही, उसने मौजूदा रोजगार को चुनौती देने के साथ-साथ देश के समक्ष कठिन नीतिगत चुनौतियां भी पैदा की हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे देश में रोजगार एक बड़ी समस्या है। ऐसे में नई सरकार कैसी नई औद्योगिक नीति बनाएगी?

सरकार का राष्ट्रीय खुदरा कारोबार नीति बनाने का वादा भी संभावनाओं से भरपूर है। इस नीति का लक्ष्य होगा खुदरा कारोबार को बढ़ावा देना परंतु विदेशी निवेशक और बड़ी भारतीय कंपनियां भी इस पर नजर रखेंगी। मोदी सरकार की संगठित खुदरा नीति खासतौर पर विदेशी निवेश से संबंधित नीति कुछ ज्यादा ही महत्त्वाकांक्षी रही है। छोटे कारोबारी सत्ताधारी दल के जनाधार का अहम हिस्सा हैं। वे खुदरा क्षेत्र में खुलापन लाने के विरोधी हैं। बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों की आमद ने उनकी असुरक्षा बढ़ाई है।

हाल में वॉलमार्ट के भारतीय संयुक्त उपक्रम को लेकर जो खुलासे हुए हैं उनके मुताबिक कंपनी ने 2011 में कुछ भारतीय अधिकारियों को अनुचित भुगतान किया। यह बात भी खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश को लेकर मोदी सरकार के रुख को प्रभावित कर सकती है। क्या नई खुदरा नीति विदेशी निवेश के मानकों को अधिक प्रतिबंधात्मक बनाएगी या इस क्षेत्र में खुलापन लाते हुए खुदरा कारोबारियों को कुछ अन्य प्रोत्साहन दिया जाएगा?

उद्यमियों की पूंजी की जरूरत का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार उन्हें 50 लाख रुपये तक का ऋण बिना किसी गारंटी के प्रदान करेगी। बिना गारंटी के इतना अधिक ऋण वित्तीय क्षेत्र की सेहत के लिए ठीक नहीं है। बैंकों ने फंसे कर्ज से निपटना शुरू ही किया है। ऐसे में बिना गारंटी के 50 लाख रुपये तक का ऋण राजनीति से प्रभावित ऋण की राह खोल सकता है। इसकी अदायगी अनिश्चित होगी। खेद की बात है कि ऐसे ऋण का बोझ भी सार्वजनिक क्षेत्र के उन बैंकों को उठाना होगा, जो पहले ही संकट के दौर से गुजर रहे हैं। क्या सरकार एक अलग नाम से ऋण मेला शुरू करने जा रही है?

## कानाफूसी

### कम हो आक्रामकता

पिछले दिनों राजधानी दिल्ली में पुलिसकर्मियों के एक समूह पर तलवार से हमला करने वाले व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा और मारपीट भी की। यह पूरी घटना कैमरे में कैद हुई और उसे कई जगह साझा भी किया गया। व्यक्ति ने पुलिस पर हमला कर उसे भड़काया था लेकिन दिल्ली पुलिस के कई अधिकारियों का मानना है कि पुलिस की प्रतिक्रिया उचित नहीं थी और इससे उसकी छवि को धक्का पहुंचा है। पुलिस के आक्रामक व्यवहार का एक कारण यह भी है कि कई युवा सिपाहियों को भर्ती के बाद बिना जनता से निपटने का प्रशिक्षण दिए सीधे बीट कॉन्स्टेबल बनाकर थाने भेज दिया गया। प्रशिक्षण के बिना जनता के बीच जाने से ऐसी हिंसा की घटनाएं हो सकती हैं। विचार हो रहा है कि नए जवानों को पहले बटालियन में भेजा जाए जहां वे वरिष्ठों के बीच कानून व्यवस्था से निपटना सीख सकें। उसके बाद ही उन्हें थाने में पदस्थापना दी जाए।

### चौधरी का हास्यबोध

लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी पांच बार के लोकसभा सदस्य अवश्य हैं लेकिन उनके पास केवल मैट्रिक की डिग्री है। पार्टी में कम से कम दो से तीन ऐसे नेता हैं जिन्हें लगता है कि खुद उन्हें लोकसभा में पार्टी का नेता बनाया जाना चाहिए था लेकिन संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी की रजामंदी को देखते हुए यह दायित्व चौधरी को सौंप दिया गया। सोमवार को चौधरी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापन के दौरान पार्टी की ओर से प्रमुख वक्ता थे। इस दौरान एक बार तो उन्होंने प्रधानमंत्री का लगभग अपमान ही कर दिया। बाद में उनकी टिप्पणी को कार्यवाही से बाहर कर दिया गया। हालांकि हास्यबोध से भरे उनके भाषण ने तमाम लोगों का दिल भी जीता। भाषण के बाद बगल में बैठी सोनिया गांधी ने उन्हें बधाई दी और अन्य लोगों से कहा कि वह उनके बाजू में इसीलिए बैठी रहीं।

## आपका पक्ष

### कैसे पूरा होगा मुफ्त पानी का वादा

सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को उसके घर में 24 घंटे साफ पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने करीब 600 करोड़ रुपये की लागत वाले एक जल शोधन संयंत्र का भी शिलान्यास किया जो तीन साल में बनकर तैयार होगा और इससे रोजाना 47.7 करोड़ लीटर पानी मिलेगा। राज्य सरकार का कहना है कि इस संयंत्र से राजधानी के करीब 22 लाख लोगों को 24 घंटे साफ पानी उपलब्ध होगा। हालांकि फिलहाल 24 घंटे पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना महज एक वादा मालूम होता है। अभी भी दिल्ली के किनारों पर बसीं बहुत सी बस्तियों में किसी भी तरह का पानी उपलब्ध नहीं है और वहां रह रहे लोगों को लंबी दूरी तय करके रोज पानी का प्रबंध करना पड़ता है। भीषण गर्मी में यह समस्या और विकट हो गई है। तेज गर्मी से

जगह-जगह पानी के स्रोत सूख रहे हैं और भूजल के स्तर में भी गिरावट आई है। केंद्र सरकार भी इसी तरह की एक योजना 'नल से जल' लेकर आ रही है जिसमें साल 2024 तक प्रत्येक घर में पाइप से पीने योग्य जल उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्र भी इस योजना पर गंभीरता से काम कर रहा है। हालांकि केंद्र की योजना में मुफ्त पानी का वादा नहीं किया

**अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सभी घरों में 24 घंटे मुफ्त पेयजल देने का वादा किया**

गया है। केजरीवाल दिल्ली वासियों को किस तरह मुफ्त में 24 घंटे पानी उपलब्ध कराने की योजना को अमलीजामा पहनाएंगे। राज्य सरकार के अनुसार इस समय दिल्ली के पास रोजाना 930 एमजीडी पानी उपलब्ध है और उसे 1,200 एमजीडी पानी की और आवश्यकता है। अब यह देखना होगा कि राज्य सरकार इस पानी की कमी को किस तरह पूरा करेगी और पिछड़ी बस्तियों तक वास्तव में योजना का लाभ पहुंचा पाएगी।

*संतोष मालवीय, मेरठ*

### सपा-बसपा का गठबंधन बिखरा

बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कहा है कि अब उनकी पार्टी भविष्य में होने वाले किसी भी चुनाव में अकेले भाग लेगी और वह समाजवादी पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव 2019 के समय हुआ गठबंधन तोड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि बसपा ने सपा के साथ सभी पुराने गिले-शिकवों को भुलाकर और 2012-17 में सपा सरकार के दलित विरोधी फैसलों, पदोन्नति में आरक्षण के विरुद्ध कार्यों तथा बिगड़ी कानून व्यवस्था आदि के मुद्दों को दरकिनार कर देश एवं जनहित में सपा के साथ गठबंधन धर्म को पूरी निष्ठा से निभाया लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद सपा के बदलते व्यवहार ने पार्टी को यह सोचने पर मजबूर किया। बसपा प्रमुख के इस बयान की गहरी समीक्षा की जा सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि लोसकभा चुनाव में इस गठबंधन से बसपा अपनी सीटें बढ़ाने में कामयाब रही लेकिन सपा को कोई अधिक फायदा नहीं हुआ। राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन के बनते-बिगड़ते समीकरण देश में राजनीतिक व्यवस्था का एक स्वरूप दिखाते हैं। राजनीतिक दल अक्सर अपने हित के लिए पुरानी सभी बातों और अपनी विचारधाराओं को भूल जाते हैं और किसी भी पार्टी से गठबंधन के लिए तैयार रहते हैं। दलों को राजनीतिक शुचिता पर ध्यान देना होगा।

**पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।**